वित्त निर्देश 31/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/4004/PFMS SNA/SNA-SPARSH/वित्त/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06/11/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः– PFMS SNA/ SNA-SPARSH केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त केंद्रांश/ राज्यांश विमुक्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

संदर्भः– 1. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2277/एल–66/2012/वित्त/बजट–4, दिनांक 2.3.2012 **(वित्त निर्देश 06/2012)**
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का पत्र क्रमांक– F.No.1(27)/PFMS/2020 दिनांक 16.2.2023 एवं समसंख्यक पत्र 13.7.2023

———00———

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 2.3.2012 द्वारा केंद्रीय क्षेत्रीय, केंद्र प्रवर्तित तथा अन्य केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं में भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त होने पर, केंद्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश विमुक्त करने के अधिकार सशर्त प्रशासकीय विभागों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। विमुक्ति की सहमति हेतु नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है।

2/ भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–16.2.2023 के अनुसार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (PFMS-SNA) हेतु राज्य शासन को केंद्र शासन से राशि प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर केंद्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि SNA खाता में अंतरण किया जाना आवश्यक है। अंतरण में विलम्ब होने पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश की राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिकी के दर से दाण्डिक ब्याज का प्रावधान किया गया है।

3/ भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–13.7.2023 द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि को SNA खाता में विमुक्त करने के साथ–साथ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में व्यय/ भुगतान की आवश्यकता अनुसार Just-in-time release के लिए PFMS SNA-SPARSH लागू किया गया है, जिसमें प्रथमतः भारत सरकार द्वारा केंद्रांश के लिए Mother Sanction जारी की जाती है, तथा राज्य शासन को भी उसी समय अनुपातिक राज्यांश की स्वीकृति जारी करते हुए RBI के e-kuber portal के माध्यम से Real Time Payment किया जाता है।

4/ **अतः राज्य शासन द्वारा प्रचलित प्रक्रिया में PFMS SNA एवं PFMS SNA-SPARSH द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आबंटन की त्वरित विमुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं के लिए सरलीकरण करते हुए केंद्रांश/ राज्यांश विमुक्ति करने का अधिकार निम्न शर्तों के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रत्यायोजित किया जाता है:–**

4.1– विमुक्त की जाने वाली राशि का बजट में उपयुक्त शीर्ष में प्रावधान हो। उदाहरणार्थ केंद्रांश हेतु सेगमेंट कोड–701/702/703 में, राज्यांश हेतु सेगमेंट कोड–704/705/706 में प्रावधान हो उपरोक्त शीर्ष अंतर्गत प्रावधान न होने पर यथासमय प्रावधान हेतु वित्त विभाग को यथोचित प्रस्ताव प्रेषित करे।

4.2– भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रांश एवं अनुपातिक राज्यांश विमुक्त की जाए। जब तक केंद्रांश की प्राप्ति न हो वित्त विभाग की बिना सहमति के राज्यांश की विमुक्ति न की जाए।

4.3– प्रशासकीय विभाग Off-Budget के रूप में प्राप्त केंद्रांश राशि की पुष्टि अपने स्तर से करे एवं उसी अनुपात में राज्यांश विमुक्ति सुनिश्चित की जाए।

4.4– PFMS SNA द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत केंद्र शासन से राशि प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर केंद्रांश एवं आनुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्ति सुनिश्चित की जाए। अंतरण में विलम्ब होने पर विभाग की जिम्मेदारी होगी।

4.5– विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की गयी विमुक्ति आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग के बजट शाखा–04 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

5/ **उपरोक्त कंडिका 4 अनुसार व्यवस्था PFMS SNA/ SNA-SPARSH केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगी।** शेष अन्य योजनाओं के लिए केंद्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति की प्रक्रिया वित्त निर्देश 06/2012 अनुसार रहेगी। जिन योजनाओं में केंद्रांश एवं अनुपातिक राज्यांश के अतिरिक्त राशि (टॉप अप) राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उक्त राशि वित्त विभाग की अनुमति से ही विमुक्त की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

4005
पृष्ठां.क्र./ /PFMS SNA/SNA-SPARSH/वित्त/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उपसचिव/अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/ अपर सचिव /संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेवसाईट www.finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

(उत्कल कुमार शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

महत्वपूर्ण

वित्त निर्देश 06/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक/2277/एल–66/2012/वित्त/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 02.03.2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः–केन्द्रीय क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा भारत सरकार के आयोजनागत एवं आयोजना भिन्न अनुदान के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

———————

प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तथा भारत सरकार के आयोजनागत अनुदान (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुच्छेद 275(1), बाह्य सहायता प्राप्त अनुदान आदि) एवं आयोजना भिन्न अनुदान (पुलिस बल आधुनिकीकरण, राज्य आपदा निधि आदि) के अंतर्गत जारी केन्द्रांश तथा उससे संबद्ध राज्यांश की विमुक्ति हेतु प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि योजना अंतर्गत व्यय करने से पूर्व यह सत्यापन/पुष्टि कर ली जाए कि प्राप्त आवंटन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है तथा उक्त योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त होकर राज्य शासन के खाता में जमा हो चुकी है।

2. उपर्युक्त योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवंटन की त्वरित विमुक्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ***राज्य शासन द्वारा प्रचलित प्रकिया में सरलीकरण करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था अनुसार केन्द्रांश/राज्यांश की विमुक्ति के लिए वित्त विभाग की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए प्रशासकीय विभाग को निम्न शर्तों के अधीन केन्द्रांश/राज्यांश विमुक्ति करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता हैः–***

2.1 ***विमुक्त की जाने वाली राशि का बजट में उपयुक्त शीर्ष में प्रावधान हो।*** कतिपय योजनाओं में बजट प्रावधान से अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है। ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान करने के पश्चात् ही विमुक्ति की कार्यवाही की जाए।

2.2 ***केन्द्रीय योजनाओं की राज्य बजट के माध्यम से जारी होने वाली राशि भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के अनुरूप राज्य शासन के खाता में जमा हो गयी हो।*** यह जानकारी वित्त विभाग की वेबसाईट www.cgfinance.nic.in में दैनिक आधार पर अपलोड कराया जाता है। वेबसाईट में जाकर इसे देखने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाये :–

2.2.1 सर्वप्रथम वित्त विभाग के वेबसाईट www.cgfinance.nic.in को खोलें।

2.2.2 होमपेज के बायें मार्जिन पर " Release from Government of India" को क्लिक करें।

2.2.3 इसके पश्चात् "Release" को क्लिक करें।

2.2.4 "Scheme wise" को क्लिक करें एवं आवश्यकता अनुसार अवधि चुने ।

2.2.5 संबंधित योजना (जैसे RKVY) को क्लिक करें जिसमें भारत सरकार का स्वीकृति आदेश कमांक, दिनांक तथा विमुक्त एवं राज्य शासन में जमा राशि का विवरण दर्शाया गया है।

2.2.6 उपरोक्त अनुसार कार्यवाही में कोई कठिनाई हो तो वित्त विभाग के शोध अधिकारी श्री प्रशांत लाल (दूरभाष नंबर 4049445) से संपर्क किया जा सकता है।

2.3 ***भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुपात में ही राज्यांश विमुक्त की जाए,*** अर्थात् भारत सरकार द्वारा अगर प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गयी हो, तो राज्यांश का भी 50 प्रतिशत राशि विमुक्त की जाए।

2.4 कतिपय केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश off-budget के रूप में प्राप्त होती है एवं इस राशि के विरूद्ध राज्यांश का प्रावधान बजट में रखा जाता है । इन योजनाओं का विवरण वित्त विभाग के बेवसाइट में उपलब्ध नहीं रहता है । ***ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय विभाग off-budget के रूप में प्राप्त राशि की पुष्टि अपने स्तर से करें एवं उसी अनुपात में ही राज्यांश विमुक्त सुनिश्चित की जाएं।***

2.5 ***विमुक्त की जाने वाली राशि से संबंधित योजना सक्षम स्तर से अनुमोदित हो तथा व्यय के मदों हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुरूप सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाये।***

2.6 विषयांकित योजना के अंतर्गत विमुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग उपर्युक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लें। ***तद्नुसार इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश–राज्यांश विमुक्त करने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा एवं इसके लिए नस्ती वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।***

3. प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की गयी विमुक्ति आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग के बजट शाखा–04 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।

4. ***यह संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।***

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त तथा योजना विभाग

पृष्ठां. कमांक/2278/एल–66/2012/वित्त/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 02.03.2012

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, रायपुर
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वित्त विभाग

F. No. 1(27)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
PFMS Division

North Block
New Delhi, 13th July, 2023

To

Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance): All States/UTs

Subject:"Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber platform of Reserve Bank of India (RBI).

Sir/Madam

The General Financial Rule 232(v) prescribes the release of funds to the State Governments and monitoring utilization of funds through PFMS. For better monitoring the availability and utilization of funds released to the States under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and to reduce float, the Department of Expenditure vide OM No. 1(13)PFMS/FCD/2020 dated 23rd March, 2021 has issued guidelines for revised procedure for flow of funds under CSS. The revised procedure, known as the "SNA model", came into effect from 1st July, 2021.

2. Further, in view of rule 230 (7) of GFR 2017 which prescribes that "The principles of 'just in time release' should be applied for releases in respect of all payments to the extent possible" and to bring about more efficiency in cash management at both Centre and States level, it has been decided to introduce an alternative fund flow mechanism named SNA – SPARSH (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण – Real time System of Integrated Quick Transfers) for CSS funds through an integrated framework of PFMS, State IFMIS and e-kuber platform of Reserve Bank of India (RBI) in a progressive manner. The names of schemes and States to be covered by the alternative fund flow mechanism will be notified from time to time.

3. Following procedure will be followed by the State Governments concerned and the Ministries/Departments of the Government of India for the schemes notified for implementation in SNA –SPARSH model -

i. Ministry/Department concerned of the Government of India shall open a drawing account with RBI under the existing User Defined Customer Hierarchy (UDCH) code of the Ministry/Department concerned.

ii. The State Government will designate a Single Nodal Agency (SNA) for implementing each State Linked Scheme (SLS) corresponding to a CSS. Existing SNAs under the "SNA model" may also be designated as SNAs under SNA- SPARSH model.

iii. The State Government shall open SLS wise drawing accounts of SNA in RBI. Before opening of drawing account of an SLS, State Government and Ministry/Department concerned of GoI shall ensure that the Centre-State fund sharing ratio is uniform under all components of that SLS. In case of Umbrella schemes having multiple sub schemes/components with varying sharing patterns, State Governments in consultation with Ministry/Department concerned should open separate SLS for sub schemes/components with different sharing ratio.

iv. After opening of aforesaid drawing accounts in RBI by the Ministries/Departments and the State Governments, the Ministries/Departments and the State Governments will approach the PFMS division, O/o CGA for on boarding the scheme onto SNA-SPARSH platform of PFMS by 'marking' of the CSS on PFMS. Simultaneously, the State Governments shall map the CSS with corresponding SLSs as per the existing protocol.

v. Upon on boarding of a scheme onto SNA- SPARSH platform, the State Government shall close all the SNA accounts pertaining to the scheme and return the Central share of unspent balance lying in the SNA accounts to the Consolidated Fund of India (CFI). Similarly the State share of unspent balance in the SNA accounts should be returned to the Consolidated Fund of the State. Further, the central share under the scheme lying in State treasury should also be returned to the CFI. Detailed procedure for calculation and return of the unspent amount will be issued separately.

vi. Once a CSS is on boarded onto SNA-SPARSH platform of PFMS, Ministry/Department concerned shall use only the SNA- SPARSH platform to release funds under the scheme as per the guidelines contained in this OM and further guidelines issued in the matter. The use of SNA platform to release funds as per DoE's guidelines dated 23rd March, 2021 shall be stopped immediately after on boarding of the CSS onto SNA- SPARSH platform.

vii. In the beginning of a financial year, the Ministries/Departments will create a 'mother sanction' in PFMS for a State for a CSS. The 'mother sanction' will define State wise drawing limit of the Ministry/Department for that CSS. The mother sanction may be modified by the Ministry during the year with the concurrence of the IFD.

viii. The SNA and the Implementing Agencies (IAs) down the ladder shall be registered in State Integrated Financial Management Information System (State IFMIS).

ix. Whenever the SNA/IAs needs to make payment to vendors/beneficiaries, the SNA/IA will generate payment files in State IFMIS. The payment files generated by SNA/IAs will be consolidated by State treasury in State IFMIS periodically after thorough scrutiny.

x. In the case of States where the IT system is not ready to onboard a large number of agencies with proper protocol, the agencies may submit manual claims to State treasury which in turn shall process these claims in the State IFMIS.

xi. State Government will develop a State Cyber Treasury wherein all payment files with SLS tags from the SNA/IAs could be received for payment and the vouchers could be compiled for accounting purpose. The State Cyber Treasury shall make the provision of 'flags' to identify the SNA/IA which has raised the claim and the SLS to which the claim pertains to.

xii. State Government/treasury will share the consolidated payment file with PFMS for advance release of Central share.

xiii. After receiving the consolidated payment file on PFMS, the Ministry/Department concerned will generate a sanction equivalent to the central share specified for the SLS on PFMS and transfer the central share of funds from centre's drawing account to the State's drawing account. Thus, State's drawing account shall be pre-funded with central share. After release of central share of funds, the mother sanction for the centre's drawing account for the scheme for the State will be reduced by an equivalent amount.

xiv. Payment files received from State Treasury in PFMS till the cut-off time of 3 PM during a working day will be processed and sanction for the central share will be generated on the same working day. Sanction for the central share for payment files received beyond the cut-off time of 3 PM may be generated on the next working day.

xv. Upon receipt of Central share, the consolidated payment file in State IFMIS will be auto pushed from State IFMIS to RBI. RBI shall debit the State's drawing amount by the total amount of the payment file and release payments to vendors/beneficiaries as per the instructions contained in the payment file. RBI will share the Debit notification of this payment with both PFMS and State IFMIS.

xvi. In some schemes, the State Governments are releasing 'top up' amount in addition to the Central share and State share. State IFMIS and PFMS shall maintain a master database of proportion of Central, State share and the top up amount in such schemes. Payment files of such schemes will mandatorily include the 'top up' amount separately in line with the proportions in the master database and the Central share will not be calculated on the 'top up amount'. In case of schemes having 'top up' by State Government, Ministries/Departments shall not generate the sanction for central share against the payment files which are not reflecting the top up amount separately.

xvii. There shall be periodic reconciliation and settlement of funds including failed transactions between Centre and State. The consolidated payment file pushed by State IFMIS to PFMS will mandatorily have the flagging for reinitiated transactions against previously failed transactions (if applicable) to avoid duplicate payments.

xviii. Funds will remain in respective consolidated funds and will be released to the beneficiaries/vendors just in time. The funds will not be diverted to any Personal Deposit (PD) account or any other account by the State Government.

xix. UTs without legislature work directly in PFMS and there is no need for them to open account in RBI. Ministries concerned can allow UTs with legislature to operate the concerned budget head through Letter of Authorization. UTs without legislature will ensure that the funds are released to the vendors/beneficiaries 'just in time' and are not parked in a bank account. In case funds are to be released to any agency as per scheme guidelines, provision of Rule 230 (vii) of GFR 2017 will be strictly followed to avoid parking of funds, with agencies.

4. This issues with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

Prateek Kr Singh 13/7/23

(Prateek Kumar Singh)
Director (PFC-I)
011-23094961
E-mail: prateeks.98@gov.in

Copy to:

1. PSO to Finance Secretary &Secretary (Expenditure)
2. PSO to Special Secretary (Pers)
3. PSO to AS(PF-S)
4. PPS to CGA
5. Sr. PPS to AS (PFC-II)
6. Sr. PPS to JS (PFC-I)

उपसचिव - 10761
06/09/23

SP

F. No. 1(27)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
PFMS Division

8 SEP 2023
Secy (Finance)

आवक / जावक क्र. 1806
सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग
दिनांक 06/09/2023

North Block
New Delhi, 4th September, 2023

To

The Chief Secretary
Government of Chhattisgarh
Raipur

Subject: "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through e-kuber platform of Reserve Bank of India (RBI) – notification of States and Schemes to be covered under the SNA SPARSH model.

The undersigned is directed to refer to this Department's guidelines issued vide DoE's OMs of even number dated 13th July, 2023 and 18th July, 2023 wherein it was decided that 2 schemes - Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA) scheme of Department of Higher Education and Swachh Bharat Abhiyan (Gramin) scheme of Department of Drinking Water and Sanitation are to be implemented as per guidelines dated 13th July, 2023 in the 5 States of Rajasthan, Karnataka, Odisha, Telengana, and Jharkhand w.e.f 1st August, 2023.

2. In this regard it has been decided to on board following **additional** 4 schemes and 5 States on the SNA SPARSH platform **w.e.f 1st October, 2023** -

i. **Schemes** -

a. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM ABHIM) of Department of Health & Family Welfare
b. Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) of Department of Fisheries
c. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana of Ministry of Women and Child Development.
d. Integrated Development of Wildlife Habitats of Ministry of Environment Forest & Climate Change

ii. **States** - Chhattisgarh, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, and Assam.

DS-3

OSD(3) PFMS 13/09/2023

OSD(1) 12/9/23

3. Therefore **w.e.f 1st October, 2023,** the aforesaid 6 schemes (2 existing and 4 additional) will be implemented as per DoE's guidelines dated 13th July, 2023 in the 10 States of Rajasthan, Karnataka, Odisha, Telengana, Jharkhand, Chhattisgarh, Gujarat, Andhra Pradesh, Bihar, and Assam.

4. This issues with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).

Prateek K Singh 4/9/23

(Prateek Kumar Singh)
Director (PFC-I)
011-23094961
E-mail: prateeks.98@gov.in

Copy to:

1. Addl CGA, PFMS, O/o CGA

F. No. 1(13)/PFMS/2020
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
******

North Block,
New Delhi, 16th February, 2023

To

Chief Secretaries/Principal Secretaries (Finance): All States/UTs

Subject: Revised procedure for flow of funds under Centrally Sponsored Schemes – Transfer of Central and State share of funds to the Single Nodal Agency (SNA) account and levy of interest for delay in such transfer.

The undersigned is directed to refer to Para No. 16 of the revised procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) issued vide this Department's letter No. 1(13)/PFMS/FCD/2020 dated 23rd March, 2021. It provides that the Central share and commensurate State share is to be transferred by the State Government to the Single Nodal Agency's (SNA) account within 21 and 40 days respectively of receipt of Central share.

2. In partial modification of the aforesaid provision in the guidelines, it has been decided by the competent authority that the State Government shall transfer the Central share as well as the commensurate State share to the SNA account within 30 days of receipt of Central share.

3. Further, it has been decided to charge interest w.e.f 01.04.2023 on the number of days of delay beyond 30 days in transfer of Central share to the SNA account at the rate of 7% per annum. PFMS division, O/o CGA will issue guidelines regarding procedure for deposit of penal interest by the State Government concerned in the Consolidated Fund of India.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

Prateek K Singh
16/2/23
(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

Copy to:

1. Secretaries to the Government of India
2. Financial Advisers to the Ministries/Departments
3. Add. CGA (PFMS) with the request to develop facility in PFMS for calculation and deposit of interest and to issue detailed SoP in this regard.
All Pr. CCAs/CCAs of all Ministries/Departments